1. मॉड्यूल और इसकी संरचना का विवरण

मॉड्यूल विवरण	
विषय नाम	अर्थशास्त्र
पाठ्यक्रम का नाम	भारतीय आर्थिक विकास 01 (कक्षा XI, सेमेस्टर - 1)
मॉड्यूल का नाम / शीर्षक	भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-1990) - भाग 2
मॉड्यूल Id	keec_10302
पूर्वअपेक्षित ज्ञान	भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूर्व-ज्ञान (1950-1990)
उद्देश्य	इस पाठ के अध्ययन के बाद, शिक्षार्थी निम्नलिखित को समझने में सक्षम होंगे: • निजीकरण • वैश्वीकरण • बहि:स्रोतन (आउटसोर्सिंग) • विश्व व्यापार संगठन (WTO) • एलपीजी नीतियों का मूल्यांकन
मुख्य शब्द	निजीकरण, वैश्वीकरण, आउटसोर्सिंग, विश्व व्यापार संगठन (WTO)

2. Development Team

Role	Name	Affiliation
National MOOC Coordinator (NMC)	Prof. Amarendra P. Behera	CIET, NCERT, New Delhi
Program Coordinator	Dr. Mohd. Mamur Ali	CIET, NCERT, New Delhi
Course Coordinator (CC) / PI	Prof. Neeraja Rashmi	DESS, NCERT, New Delhi
Subject Matter Expert (SME)	Mr. Naveen Sadhu	Guru Nanak Public School, Rajouri Garden, New Delhi
Review Team	Dr. Meera Malhan Dr. Himanshu Singh	DCAC, University of Delhi Satyawati College (Eve.), University of Delhi
Translator	Dr. Bharat Bhushan	Assistant Prof., Shyamlal College, University of Delhi

विषय-सूची:

1. निजीकरण
2. निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क
3. भूमंडलीकरण
   3.1 वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक लक्षण
   3.2 आउटसोर्सिंग
   3.3 विश्व व्यापार संगठन
4. एलपीजी नीतियों का मूल्यांकन
   4.1 आर्थिक सुधारों के पक्ष में तर्क
   4.2 आर्थिक सुधारों की आलोचना
5. सारांश

1. निजीकरण

आर्थिक सुधारों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता निजीकरण की नीति को प्रोत्साहन देना है। इस नीति के तहत, निजी क्षेत्र को विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में एक प्रमुख भूमिका निभाने की अनुमति दी गई है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था में राज्य/ सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को कम करती है।

निजीकरण का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण का हस्तांतरण निजी क्षेत्र में उद्यमियों को है।

निजीकरण का तात्पर्य है देश की आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र की अधिक भूमिका। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने कई सार्वजनिक उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया है, जिनमें **IPCL, IBP, Maruti Udyog** आदि शामिल हैं।

निजीकरण निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:

1. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन का सरकार से निजी क्षेत्र में स्थानांतरण।

2. सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी का हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण। इस प्रक्रिया को विनिवेश के रूप में जाना जाता है।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आरक्षित उद्योगों में निजी क्षेत्र के उद्योगों का प्रवेश।

4. सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे को सीमित करना और मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र का और अधिक विस्तार नहीं होना।

निजीकरण का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन में सुधार करना और आधुनिकीकरण को सुगम बनाना था। यह भी माना गया कि निजी पूंजी और प्रबंधकीय क्षमताएं सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी।

2. निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के खराब प्रदर्शन के मद्देनजर, वे भारी घाटे और बढ़ते सब्सिडी भुगतान के कारण अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ डाल रहे थे। निजीकरण सरकार के इस वित्तीय बोझ को कम करता है। निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की एकाधिकार स्थिति को समाप्त कर देता है और इन उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार करने में मदद करता है। यह प्रबंधकीय दक्षता में सुधार करने में मदद करता है क्योंकि अब प्रबंधन अवांछित राजनीतिक प्रभाव, दबाव और हस्तक्षेप के अधीन नहीं है। अवांछित कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए कोई राजनीतिक दबाव नहीं है जो संगठन को बेहतर दक्षता की ओर ले जाता है। त्वरित और समय पर निर्णय इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। निजीकरण की नीति निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक लचीला बनाने में सहायक होगी क्योंकि प्रबंधन किसी भी सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होगा। निजीकरण के तहत उपभोक्ता सर्वोच्च है। निजी उद्यमों का अस्तित्व उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर निर्भर करता है। निजीकरण बाजार में बने रहने की आवश्यकता के कारण उपभोक्ताओं की परवाह को बढ़ावा देगा। इसलिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

इसके अलावा, निजीकरण उन क्षेत्रों को खोलता है, जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, उदाहरण के लिए बीमा क्षेत्र। यह निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक रोजगार और आय-अर्जित करने के अवसरों का सृजन होता है।

निजीकरण के खिलाफ तर्क

यह तर्क दिया जाता है कि निजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक कल्याण की उपेक्षा की जाती है। निजी क्षेत्र के उद्यम मुख्य रूप से लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से संचालित होते हैं और

यह प्रणाली गरीब लोगों के सामाजिक कल्याण की गारंटी नहीं देती है। निजी क्षेत्र उन परियोजनाओं में रुचि नहीं लेते हैं जो जोखिमपूर्ण हैं और कम लाभप्रदता के साथ लंबी अवधि की अवधि होती है। इससे देश में बुनियादी और भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विश्व बैंक के एक अध्ययन का अनुमान है कि भारत में आधारिक संरचना (infrastructure) में निवेश 1991-92 में 5.4 प्रतिशत से घटकर 1997-98 में 4.6 प्रतिशत हो गया। सरकार की भागीदारी में कमी के परिणामस्वरूप एक सार्वजनिक एकाधिकारी उद्यम का प्रतिस्थापन एक निजी एकाधिकारी उद्यम द्वारा हो सकता है, जिससे निजी मालिकों द्वारा एकाधिकारवादी शोषण हो सकता है। राज्य एकाधिकार निश्चित रूप से निजी एकाधिकार से बेहतर माना जाता है। निजीकरण के तहत, हमेशा छंटनी और परिणामस्वरूप बेरोजगारी का डर होता है। निजीकरण के कारण कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कई श्रमिकों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई है। इस तरह, यह नीति देश में बेरोजगारी और गरीबी को जन्म दे सकती है।

नवरत्न तथा मिनी रत्न

भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के संदर्भ में नवरत्नों से तात्पर्य नौ ऐसी लाभ कमाने वाली कंपनियों से है, जिनकी तुलना राजा विक्रमादित्य के दरबार में नौ दरबारियों से की जाती है, जो प्रतिष्ठित और दुर्लभ ज्ञान के व्यक्ति थे। खिताब देने का उद्देश्य प्रबंधकीय निर्णय लेने में उन्हें स्वायत्तता देकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दक्षता में सुधार करना था। उदाहरण के लिए, कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्नों और मिनी रत्न के रूप में विशेष दर्जा दिया गया है। उदाहरण के लिए, BHEL, BPCL, SAIL, आदि, उन्हें विभिन्न निर्णय लेने, कंपनी को कुशलतापूर्वक चलाने और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए प्रबंधकीय और संचालन स्वायत्तता दी गई थी। नवरत्न का दर्जा देने से इन कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ। इसके अलावा, 97 अन्य लाभ कमाने वाले उद्यमों को अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान की गई और उन्हें "मिनी रत्न" कहा गया।

जून, 2016 में, 17 नवरत्न थे, जिनके नाम हैं:

1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
5. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
8. नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड
9. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड
10. एनएमडीसी लिमिटेड
11. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12. ऑयल इंडिया लिमिटेड
13. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
16. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
17. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3. भूमंडलीकरण

'वैश्वीकरण' शब्द दुनिया के लिए अर्थव्यवस्था को शेष दुनिया के साथ जोड़ने का संकेत देता है। इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था का दुनिया के अन्य देशों के साथ उत्पादन, व्यापार और वित्तीय लेनदेन से है। वैश्वीकरण की नीति विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश दोनों को प्रोत्साहित करती है।

वैश्वीकरण का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी के आवागमन पर बाधाओं को हटाने के द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का परिणाम है। यह देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है, और यह विभिन्न नीतियों के सेट का एक परिणाम है जिनका उद्देश्य दुनिया को अधिक से अधिक परस्पर -निर्भरता और एकीकरण के लिए बदलने का है। इसमें आर्थिक,

सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है। संक्षेप में, वैश्वीकरण का लक्ष्य एक सीमारहित दुनिया बनाना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण द्वारा किए गए परिवर्तन

नई आर्थिक नीति ने उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च निवेश प्राथमिकता वाले उद्योगों की एक निर्दिष्ट सूची तैयार की, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए विदेशी इक्विटी के 51 प्रतिशत तक स्वचालित अनुमति उपलब्ध होगी। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों के संबंध में, 1 करोड़ रुपये की राशि तक उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में स्वचालित अनुमति प्रदान की जाती है। अब विदेशी तकनीशियनों को काम पर रखने या विदेशों में स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक के परीक्षण के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए, जुलाई 1991 में रुपये का लगभग 20 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया था। इसने निर्यात को प्रोत्साहित किया, आयात को हतोत्साहित किया और विदेशी पूंजी की आमद बढ़ा दी। दुनिया के साथ अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने के लिए, केंद्रीय बजट 1992-93 में भारतीय रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया और फिर 1993-94 के बजट में चालू खाते के लेनदेन में रुपये को पूरी तरह से परिवर्तनीय बनाया गया। भारत के विदेशी व्यापार के वैश्वीकरण के ढांचे को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा पांच साल के निर्यात-आयात नीति (1992-97) की घोषणा की गई थी। इस नीति ने बाहरी व्यापार से सभी प्रतिबंधों और नियंत्रणों को हटा दिया और बाजार शक्तियों को निर्यात और आयात के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति दी। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दायरे में लाने के लिए, सरकार ने सीमा शुल्क को काफी हद तक संशोधित किया है। तदनुसार, 2007-2008 के बजट में कुछ सामानों पर सीमा शुल्क की अधिकतम दर 250 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

3.1 वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष

उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारत और अन्य देशों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम उत्पन्न किए हैं।

वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क

1. वैश्वीकरण के कारण संसाधनों की आवंटन क्षमता में सुधार हुआ है, पूंजी उत्पादन अनुपात घटा है और विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ा है। इसने देश में प्रौद्योगिकी को भी उन्नत किया और अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर में भी वृद्धि हुई। इसने देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि की। परिणामस्वरूप भारत के विदेशी व्यापर में वृद्धि हुई। वास्तव में, भारत जैसी श्रम प्रचुर और पूंजी की कमी वाली अर्थव्यवस्था में उत्पादन और व्यापार के पुनर्गठन में मदद की। इसने विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि और अवसर को बढ़ाया है। देश में सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले उपभोक्ता सामान का आयात तकनीक के साथ किया जाएगा। विदेशी पूंजी और विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा के साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ है।

वैश्वीकरण के खिलाफ तर्क

कुछ विद्वानों द्वारा वैश्वीकरण की आलोचना की गई है क्योंकि विकसित देशों ने वैश्वीकरण के लाभों को अधिक अर्जित किया, क्योंकि वे अन्य देशों में अपने बाजारों का विस्तार करने में सक्षम थे। वास्तव में वैश्वीकरण, गरीब देशों के लोगों के कल्याण और पहचान से समझौता करता है। बाजार-संचालित वैश्वीकरण राष्ट्रों और लोगों के बीच आर्थिक विषमताओं को बढ़ाता है। सभी देश अपने स्वयं के क्षेत्रों के बाहर विकास के लिए असुरक्षित हो गए हैं।

3.2 आउटसोर्सिंग

यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। यह बाहरी दुनिया से व्यावसायिक सेवाओं को काम पर रखने की एक प्रणाली है। इन सेवाओं में शामिल हैं: कॉल सेंटर, ट्रांसक्रिप्शन, नैदानिक सलाह, शिक्षण / कोचिंग आदि।

भारत विशेष रूप से आउटसोर्सिंग के एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभर रहा है, बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे कॉल सेंटर भी कहा जाता है)। इसका कारण (i) भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता, या कुशल श्रमिकों के लिए अपेक्षाकृत कम मजदूरी दर, और (ii) भारत में आईटी उद्योग का क्रांतिकारी विकास है।

जिन सेवाओं को भारत की कंपनियों द्वारा आउटसोर्स किया जा रहा है, उनमें वॉयस-आधारित व्यावसायिक प्रक्रियाएं (जिन्हें बीपीओ या कॉल सेंटर के रूप में जाना जाता है); रिकॉर्ड रखना;

लेखा; बैंकिंग सेवाएं; संगीत रिकॉर्डिंग; फिल्म का संपादन; पुस्तक प्रतिलेखन; नैदानिक सलाह, आदि शामिल हैं ।

3.3 विश्व व्यापार संगठन (WTO)

व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता (GATT) 1948 में 23 देशों के साथ एक वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। GATT की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को लागू करने के लिए की गई थी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में गैट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य में डब्ल्यूटीओ समझौते लिए वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं में व्यापार को भी शामिल करते हैं। वर्तमान में, विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य देश हैं और सभी सदस्यों के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत बनाए गए कानूनों और नीतियों का पालन करना आवश्यक है। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, भारत निष्पक्ष वैश्विक नियमों, विनियमों और विकासशील दुनिया के हितों की वकालत करने में सबसे आगे रहा है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है। भारत ने आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाकर और टैरिफ दरों को कम करके व्यापार को उदार बनाने के लिए उचित कदम उठाए हैं।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य:

(i) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार दोनों) को बढ़ाने के लिए प्रशुल्क के साथ-साथ गैर- प्रशुल्क बाधाओं को दूर करना;

(ii) नियम-आधारित व्यापारिक प्रणाली स्थापित करना, जिसमें राष्ट्र व्यापार पर मनमाना प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं;

(iii) सेवाओं का उत्पादन और व्यापार बढ़ाना;

(iv) विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना;

(v) पर्यावरण की रक्षा करना, तथा

(vi) सदस्य देशों को व्यापार और प्रशुल्क से संबंधित भविष्य की रणनीतियाँ तय करने के लिए एक मंच प्रदान करना।

4. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (आर्थिक सुधार) की नीतियों का मूल्यांकन

आर्थिक सुधारों ने विभिन्न स्तरों पर मिश्रित प्रभाव पैदा किये । आइए हम आर्थिक सुधारों के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करें।

4.1 आर्थिक सुधारों के पक्ष में तर्क

आर्थिक सुधारों के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण तर्क निम्नलिखित हैं:

1. उच्च विकास दर: जीडीपी की वृद्धि दर 1980-91 के दौरान 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 1992-2001 के दौरान 6.1 प्रतिशत और 2007-12 में 8.2 प्रतिशत हो गई। इससे पता चलता है कि सुधार की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में वृद्धि हुई है। सुधार की अवधि के दौरान, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि दर में गिरावट आई है, जबकि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर बढ़ी है। यह इंगित करता है कि विकास मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में वृद्धि से प्रेरित है। वर्तमान में, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेजी से वृद्धि: नई आर्थिक नीति के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार 1990-91 में 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से और 2015-16 में 350 अरब डॉलर हो गए हैं।

3. निर्यात में वृद्धि: 1990-91 के बाद से भारत के निर्यात और आयात का मूल्य काफी बढ़ गया है। भारत के ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग सामान, आईटी सॉफ्टवेयर और कपड़े के निर्यात में काफी वृद्धि हुई ।

4. मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: उत्पादन में वृद्धि, कर सुधारों और अन्य सुधारों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता की। 1991 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 17 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से घटकर 2012-13 में लगभग 7.6 प्रतिशत हो गई।

5. निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि: 1991 के बाद से, निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लाइसेंसिंग प्रणाली की समाप्ति और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के प्रवेश पर प्रतिबंधों को हटाने से निजी क्षेत्र के संचालन का क्षेत्र बढ़ा है।

6. औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन: औद्योगिक क्षेत्र 2003-04 से 8 प्रतिशत से अधिक विकास दर दर्ज़ कर रहा है। इसने बारहवीं योजना के दौरान 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज़ की ।

4.2 आर्थिक सुधारों की आलोचना

आलोचकों ने नए आर्थिक सुधारों की काफ़ी आलोचना की है, खासकर रोजगार, कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे के विकास और राजकोषीय प्रबंधन के क्षेत्रों में।

हालांकि सुधारों की अवधि में जीडीपी विकास दर में वृद्धि हुई है, लेकिन इस तरह की वृद्धि देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में विफल रही। हम कह सकते हैं कि यह नीति रोज़गार-रहित विकास की ओर ले जाती है। नई आर्थिक नीति ने उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की है।

कृषि क्षेत्र में, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश, जिसमें सिंचाई, बिजली, सड़क बाजार संपर्क और अनुसंधान शामिल हैं, में सुधार अवधि में कमी आयी है। खाद पर सब्सिडी को हटाने से उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई, जिससे छोटे और सीमांत किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटाने, और कृषि उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को उठाने की नीतियों का भारतीय किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का सामना करना पड़ा। कृषि में निर्यातोन्मुखी रणनीतियों के कारण, निर्यात बाजार के लिए खाद्यान्न से नकदी फसलों में उत्पादन स्थानांतरित हो गया। इससे खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हुई।

वैश्वीकरण के कारण विकसित देशों से माल और पूंजी का अधिक प्रवाह हुआ और परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योगों को आयातित वस्तुओं का सामना करना पड़ा। सस्ते आयात ने घरेलू सामानों की मांग को प्रतिस्थापित और घरेलू निर्माताओं को आयात से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसने औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी धीमा हो गया। इसके अतिरिक्त, बिजली की आपूर्ति सहित बुनियादी ढांचे की सुविधाएं निवेश की कमी के कारण अपर्याप्त हैं। वस्त्र और कपड़ों के निर्यात पर सभी कोटा प्रतिबंधों को भारत से हटा दिया गया है। लेकिन कुछ विकसित देशों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से वस्त्रों के आयात पर अपना कोटा प्रतिबंध नहीं हटाया है।

सरकार की विनिवेश नीति सफल नहीं रही, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की परिसंपत्तियों को कम मूल्य पर आंका गया था और उन्हे निजी क्षेत्र को सस्ती दरों पर बेचा गया था। इसके अलावा, विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग सार्वजनिक उपक्रमों के विकास और देश

में सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उपयोग करने के बजाय सरकारी राजस्व में कमी को पूरा करने में किया जाता है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हावी हैं। वे भारतीय बाजारों का शोषण कर रही हैं और अपने उत्पादों को बेच रही हैं। वे इस प्रकार भारी मुनाफा कमा रही हैं। भारतीय कई बार बाजार में विभिन्न वैश्विक ब्रांडों पर अपना पैसा बर्बाद करते हैं। नई नीति विलासिता की वस्तुओं और बेहतर उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करके उपभोक्तावाद की एक खतरनाक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर रही है। कृषि और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजाय जो देश के लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, यात्रा और आतिथ्य सेवाओं, वास्तविक सम्पदा और व्यापार जैसे सेवा क्षेत्र के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही विकास को केंद्रित किया गया है।

5. सारांश

नई आर्थिक नीति 1991 को कभी-कभी एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) भी कहा जाता है। इन सभी नीतियों के संयोजन ने कुछ सकारात्मक और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक परिणाम उत्पन्न किए हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी ताले खोलने के लिए यह एक रामबाण नहीं है। यह गरीबी, आय की असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है।

नई आर्थिक नीति (NEP) 1991 के बाद से, भारत के व्यापार संतुलन (निर्यात और आयात) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रुझान में काफी बदलाव दिखा। भारत विश्व व्यापार में अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है। हाल के दिनों में वैश्विक बाजारों तक पहुंच, उच्च प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास के कारण, भारत अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है।